# सीएम ने पूछा, किसने बनाया एक्वा मेट्रो का गलत रूट

## नोएडा-ग्रेनो के बीच घाटे में चल रही मेट्रो पर जताई नाराजगी तो अधिकारी बोले, बॉटनिकल गार्डन से जोड़ने की है तैयारी

Shyam.Vir
@timesgroup.com

■ **ग्रेटर नोएडा :** घाटे में चल रही एक्वा लाइन मेट्रो के रूट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने ग्रेटर नोएडा दौरे के दौरान नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि यह गलत रूट किसने बनाया? गलत रूट था तो कोच क्यों खरीदे गए? उन्होंने इस घाटे की भरपाई और इस रूट पर यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए एक्वा लाइन को नोएडा में बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर ब्लू लाइन से जोड़ने की योजना को जल्द अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए।

सीएम तीनों अथॉरिटी की समीक्षा बैठक में शुक्रवार को ग्रेनो आए थे

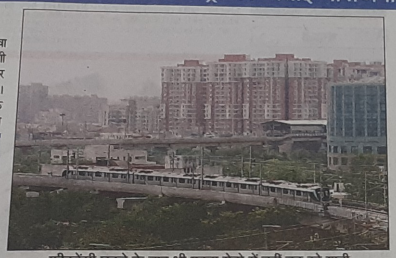

फ्रीक्वेंसी घटने के बाद भी एक्वा मेट्रो में नहीं बढ़ रहे यात्री

### सीएम ने रूट मसले पर लगा दी सवालों की झड़ी

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सभागार में शुक्रवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीनों अथॉरिटी की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। मेट्रो को लेकर उन्होंने खासतौर पर पूछा कि यह कैसी चल रही है। इस मेट्रो का सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही 25 जनवरी को लोकार्पण किया था। अधिकारियों ने सीएम को अवगत कराया कि यह घाटे में चल रही है। यात्री कम हैं। सीएम ने पूछा कि यात्री कम क्यों हैं? इस पर अधिकारियों ने इसके गलत रूट का हवाला दिया। इससे सीएम नाराज हो गए। उन्होंने पूछा कि अगर पिछली सरकार में गलत रूट बना था तो अपनी सरकार आने के बाद इसके लिए कोच क्यों खरीदे गए? सीएम ने अधिकारियों से पूछा कि अब इस रूट को लाभ में लाने के लिए वह क्या कर रहे हैं?

### यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए किए गए उपाय बताए

■ एक्वा लाइन को लेकर सीएम के सवालों पर अधिकारियों ने इस रूट पर यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए अब तक किए उपाय बताए। सीएम को बताया गया कि इस रूट से लोगों को जोड़ने के लिए फीडर बसें चलाने और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के साथ अन्य उपायों के बारे में जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि एक्वा लाइन को एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर-147 से सीधे नोएडा में बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर ब्लू लाइन से जोड़ने की योजना है। यह एरिया नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजा दिया गया है। सीएम ने इसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए रूट को जल्द बनाया जाए। जो औपचारिकताएं हैं, उन्हें जल्द पूरा कर लिया जाए।

### इस रूट पर महज 20 हजार यात्री रोज करते हैं सफर

■ नोएडा-ग्रेटर नोएडा की एक्वा लाइन पर इस समय पीक ऑवर्स में प्रति साढ़े सात मिनट में मेट्रो सेवा मिल रही है। इस समय इस रूट पर हर रोज करीब 20 हजार यात्री यात्रा कर रहे हैं। मेट्रो इस रूट पर हर रोज 213 फेरे लगा रही है। एक ट्रेन की क्षमता 1034 यात्रियों की है। इस तरह एक्वा लाइन मेट्रो में हर रोज 2 लाख से अधिक लोग यात्रा कर सकते हैं, लेकिन रूट सही नहीं होने से घाटा हो रहा है।

## बिल्डरों को जीरो पीरियड का लाभ देने पर रोक लगाने के दिए निर्देश

■ **विशेष संवाददाता, ग्रेटर नोएडा :** सीएम ने शुक्रवार को बिल्डरों को जीरो पीरियड का लाभ देने पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इस पॉलिसी के तहत बिल्डरों को काम बंद रहने के दौरान की अवधि में ब्याज में छूट दी जाती है। ये निर्देश राहत की आस में सीएम से मिलने पहुंचे बिल्डरों के लिए बड़ा झटका है। उधर, सीएम ने शाहबेरी मामले में लोगों को राहत न देने के संकेत दिए। सांसद डॉ. महेश शर्मा ने भी सीएम को पत्र सौंप कर शाहबेरी के अवैध निर्माण को नियमित करने की मांग उठाई थी।

समीक्षा बैठक के दौरान बिल्डरों को जीरो पीरियड का लाभ देने की बात उठाई गई। सीएम ने इस पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। बिल्डरों को ऐसे लाभ देने से तीनों अथॉरिटी को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। सीएम ने बिल्डरों से कहा है कि बायर्स ने अपने जीवनभर की गाढ़ी कमाई घर का सपना पूरा करने के लिए लगाई। लिहाजा बिल्डर और अथॉरिटी आपस में सामंजस्य पैदा कर अधिक से अधिक बायर्स को समय पर पजेशन दिलाने का बंदोबस्त करें।

**2 साल में एक लाख लोगों को दिए घर**

: बायर्स के साथ बैठक में सीएम ने कहा कि पिछले 2 साल में करीब 1 लाख लोगों को बिल्डर परियोजनाओं में फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में ही 2 वर्षों में लगभग 52 हजार फ्लैटों पर कब्जा दिलाया गया है, जबकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की स्थापना से लेकर 2016-17 तक मात्र 26 हजार बायर्स को ही घर उपलब्ध कराए गए थे। आने वाले 2 साल में भी अधिक से अधिक लोगों को पजेशन दिलाए जाएंगे। बायर्स ने आम्रपाली की परियोजनाओं को अथॉरिटीज के जरिए पूरा कराने की मांग की। इस पर सीएम ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी।

### शाहबेरी के अवैध निर्माण पर राहत नहीं

■ बैठक के बाद शाहबेरी के लोगों ने अवैध निर्माण को नियमित करने की मांग उठाई। उनके पक्ष में सांसद डॉ. महेश शर्मा ने भी मांग पत्र दिया था। सूत्रों के अनुसार, सीएम ने कहा है कि यह जमीन अथॉरिटी के अधिसूचित एरिया में है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ऐसी हालत में इसमें निवेश करने वाले लोगों ने गलत किया है। शाहबेरी संगठन के अध्यक्ष अलमास चौधरी ने बताया कि सीएम ने उन्हें एक मिनट का समय दिया। उन्होंने पुख्ता आश्वासन नहीं दिया, लेकिन कुछ समाधान निकलवाने की बात कही है। वह यहां के लोगों की पीड़ा को लेकर सोमवार को फिर से डीएम के दफ्तर जाएंगे।

### जेवर एयरपोर्ट परियोजना की बाधाएं होंगी दूर

■ **विस, ग्रेटर नोएडा :** सीएम योगी आदित्यनाथ ने यीडा सिटी में प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट की परियोजना की हर बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने परियोजना को लेकर जानकारी ली। डीएम, यमुना अथॉरिटी और नोएडा इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों ने परियोजना के संबंध में अब तक की कार्रवाई से सीएम को अवगत कराया। नायल की ओर से बताया गया कि निर्माण के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। डीएम ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। सीएम ने कहा है कि परियोजना को लेकर जमीन को जल्द अधिग्रहण किया जाए। साथ ही एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में इंडस्ट्री व अन्य निवेश कराने के प्रयास किए जाएं।

यहां प्रस्तावित है एयरपोर्ट

### लैंड पूलिंग पॉलिसी पर सकारात्मक संकेत, किसानों को होगा फायदा

■ **एनबीटी न्यूज, ग्रेटर नोएडा :** सीएम ने समीक्षा बैठक में तीनों अथॉरिटी के अधिकारियों को किसानों के हितों का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों के बेहतर भविष्य के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी तैयार करने पर बल दिया। इस नीति के तहत किसानों को लाभ होगा। देश में लैंड पूलिंग पॉलिसी कई राज्यों में लागू है। इससे संबंधित राज्यों में किसानों की हालत सुधरी है। किसान अपना कारोबार खड़ा कर रहे हैं। इस नीति के अनुसार, किसानों की जितनी जमीन अधिगृहीत की जाएगी, उसकी आधी जमीन विकसित कर उन्हें दी जाएगी। यह जमीन उसी एरिया में मिलेगी जिस एरिया में किसान की जमीन का अधिग्रहण होगा। ऐसी स्थिति में किसान उस एरिया में इंडस्ट्री, कमर्शल कॉम्प्लेक्स, इंस्टिट्यूट आदि खोल सकेंगे। मुआवजे का पैसा मिलने पर किसान गाड़ी और मकान बनाने में सारा धन खर्च कर देता है। इसके बाद वह आर्थिक संकट में फंस जाता है। उधर, किसानों की मांगों पर सीएम ने कहा कि जब तक शासन किसानों के संबंध में कोई फैसला लेता है, उससे पहले ही कुछ किसान कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट में भी शासन को जवाब देना पड़ता है। ऐसे में मामले उलझ जाते हैं। उन्होंने किसानों से भी सहयोग की अपील की।